ISSN: 0974-5823 Vol. 6 (Special Issue-2, December 2021)

International Journal of Mechanical Engineering

वैश्विक परिदृश्य में आत्मनिर्भर भारत

डॉ पूनम डागर

एसोसिएट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, भगिनी निवेदिता कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय

1.1 अध्ययन की पृष्ठभूमि

भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख खिलाड़ी बन रहा है जो आंशिक रूप से 1990 के दशक की शुरुआत से टैरिफ में कमी और अपेक्षाकृत कम गैर-टैरिफ बाधाओं को दर्शाता है। यह सूचना और प्रौद्योगिकी सेवाओं, फार्मास्यूटिकल्स और पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात में बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है। भारत के बड़े प्रवासी विदेशों में अच्छी तरह से एकीकृत हैं, नए निर्यात बाजारों को विकसित करने और प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण और जानकारी की सुविधा प्रदान करने में मदद करते हैं। हालांकि, भारत कुछ क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन कर सकता है (आहूजा 2011)। इनमें श्रम-प्रधान विनिर्माण निर्यात शामिल हैं, जहां भारत को स्पष्ट प्रतिस्पर्धात्मक लाभ है, और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश।

इन क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन से रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा और इस प्रकार विकास अधिक समावेशी होगा। इसके लिए और बुनियादी ढांचे में सुधार की आवश्यकता होगी, विशेष रूप से परिवहन और ऊर्जा प्रावधान में, उत्पाद बाजार के नियमों का आधुनिकीकरण, कौशल विकसित करना और व्यापार और निवेश के लिए बाधाओं पर पुनर्विचार करना। ओईसीडी सिमुलेशन से पता चलता है कि भारत एक प्रमुख लाभार्थी होगा, व्यापार में बाधाएं और निवेश को बहुपक्षीय रूप से कम किया जाएगा। बहुपक्षीय समझौते के अभाव में, अर्थव्यवस्था को व्यापार और निवेश के और उदारीकरण से भी लाभ होगा (हयात 2016)।

हालांकि भारत को अपने निर्यात बाजारों पर प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है, ओईसीडी सिमुलेशन का सुझाव है कि अगर भारत 20% तक व्यापार को प्रतिबंधित करने वाले टैरिफ और गैर-टैरिफ उपायों में कटौती करता है और व्यापार सुविधा में सुधार करता है, तो घरेलू उत्पादन में लगभग 3% की वृद्धि होगी, निर्यात में 14% की वृद्धि होगी। इससे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी नौकरियां पैदा होंगी।

ऐसे समय में जब दुनिया एक घातक महामारी से जूझ रही है, भारत इस संकट को एक अवसर में बदलने और अपनी लड़ाई को मजबूत करने की योजना बना रहा है । आत्मानिर्भर या आत्मनिर्भर यह शब्द 12 मई, 2020 को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन के दौरान भारत के प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा गढ़ा गया था (हयात 2016)।

उन्होंने इस अभियान को आत्म निर्भर भारत अभियान (आत्मनिर्भर भारत आंदोलन) के रूप में बुलाया। आत्मानिर्भर भारत के पांच स्तंभों को परिभाषित किया गया है - अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचा,प्रणाली, जनसांख्यिकी और मांग। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह आत्मानिर्भर बनने का समय है, हमारे स्थानीय उत्पादों के लिए मुखर और उन्हें वैश्विक बनने का समय है। इस अभियान के तहत सरकार द्वारा विशेष आर्थिक पैकेज जारी किया गया है, जो कुटीर उद्योग, सूक्ष्म, लघु और सहित विभिन्न क्षेत्रों को लाभ मजबूत बनाने में मदद करेगा (ओटो-ज़िम्मरमैन 2001)। इस लेख में, हम राष्ट्र के संदर्भ में आत्मनिर्भरता की धारणा का बहुत सीमित तरीके से पता लगाएंगे। एक ओर, 'आत्मनिर्भरता' शब्द को थोड़ा दार्शनिक प्रतिबिंब की आवश्यकता है क्योंकि इसके अर्थ स्पष्ट रूप से स्पष्ट हैं। वास्तव में, इस शब्द के हमारे सामान्य उपयोग में, 'स्व' शब्द बहुत कम भूमिका निभाता है।

यह मुख्य रूप से अंदर-बाहर के संदर्भ में कार्य करता है: आत्मनिर्भरता का अर्थ बाहर (दूसरों) पर निर्भर न होने के अलावा और कुछ नहीं है, लेकिन यहां तक कि इस सरल अर्थ में अंदर-बाहर, स्वयं-अन्य आदि के बारे में गहरी धारणाएं हैं (ग्लोबल फ़ोरम 2011)। जबकि यह इस शब्द का एक सामान्य उपयोग है, इस निबंध में यह समझा जाएगा कि स्वयं से संबंधित कई अर्थों का एक छिपा हुआ कार्य है। आत्मनिर्भरता के बारे में कई अलग-अलग प्रश्नों में स्वयं के बारे में ये कई दृष्टिकोण और विरोधाभास उत्पन्न होते हैं। 'स्व' के अर्थ को समझने के कई अलग-अलग तरीके हैं, ऑटोलॉजिकल से लेकर नैरटोलॉजिकल तक।

1.2 अध्ययन का महत्व

महामारी ने हमारी रोजमर्रा की प्रथाओं के संदर्भ में आत्मनिर्भर होने का क्या मतलब है, इस पर नए सिरे से विचार किया है। राष्ट्र भी आत्मनिर्भरता के अपने दावों में इस तर्क का पालन करते हैं। यह पत्र राष्ट्र के संदर्भ में आत्मनिर्भरता के इन दावों के निहितार्थों पर चर्चा करता है, इस दावे को स्वयं के दो अलग-अलग योगों के बीच तनाव के बीच रखता है: राष्ट्र का आत्म राष्ट्रीय स्व के विचार के खिलाफ (बरगवी 2017)। हालाँकि इन दिनों विश्व स्तर पर आत्मनिर्भरता के लिए एक बढ़ा हुआ धक्का है, आत्मनिर्भर होने का विचार एक लंबा है। स्वतंत्रता आंदोलन और स्वशासन के बीच का संबंध राजनीतिक आत्मनिर्भरता की अभिव्यक्ति है। भारत और अन्य जगहों पर सरकारों द्वारा आत्मनिर्भरता का नवीनतम आह्वान मुख्य रूप से आर्थिक आत्मनिर्भरता के बारे में है, लेकिन भारतीय मामले की तरह यह विशेष रूप से विनिर्माण क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के बारे में है।

लेकिन आत्मनिर्भरता की प्रकृति ऐसी है कि आत्मनिर्भरता के अन्य रूपों के बिना आर्थिक आत्मनिर्भरता को समझना मुश्किल है, सबसे महत्वपूर्ण बात, 'आत्मनिर्भरता' और साथ ही 'बुद्धि' की आत्मनिर्भरता (क्रूज़,2015)। यह विचारों की यह श्रेणी है जो आत्मनिर्भरता में मौजूद है जिसे समझने की आवश्यकता है, यहां तक कि विनिर्माण या अन्य आर्थिक प्रक्रियाओं में आत्मनिर्भरता की संकीर्ण दृष्टि के लिए भी। राष्ट्र की आत्मनिर्भरता के संदर्भ में, एक नई वैचारिक चुनौती है जिसका हमें सामना करना पड़ता है।

COVID-19 महामारी ने एक विशेष समस्या पैदा कर दी है जिसका संबंध स्वयं और समाज के बीच से है। सामाजिक पूर्व COVID-19 एक ऐसा क्षेत्र था जो व्यक्तिगत हितों को पूरा करता था - सुरक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और यात्रा से लेकर खरीदारी तक। महामारी ने वास्तव में सामाजिक दुनिया तक हमारी पहुंच को नष्ट कर दिया, एक ऐसी दुनिया जिसमें दूसरों ने दूसरों की ओर से अपना काम किया। श्रम स्वयं उन कार्यों को वितरित करने के इस कार्य के इर्द-गिर्द उन्मुख था जो किसी को स्वयं के लिए करना था। रेस्तरां ने व्यक्ति के स्वयं के भोजन पकाने की आवश्यकता का ध्यान रखा, स्कूलों ने बच्चों की देखभाल की (कम से कम दिन के एक बड़े हिस्से के लिए), अस्पतालों ने स्वास्थ्य पर नियंत्रण किया (जिनमें से अधिकांश स्वयं व्यक्तियों के हाथों में हो सकता था) और इसी तरह (क्रूज़, 2015)।

पूर्व-सीओवीआईडी हम एक ऐसा समाज थे जिसने निर्भरता के माध्यम से परिभाषित सामाजिक की भावना को तेजी से विकसित किया। यह कोई सामाजिक नहीं था जो दोस्ती या रिश्तेदारी के माध्यम से या एक सामान्य लक्ष्य की दिशा में काम करने वाले सदस्यों के रूप में एक साथ आया हो। समाज स्वयं न केवल एक सेवा अर्थव्यवस्था बल्कि एक सेवा समाज की ओर अधिक से अधिक बढ़ रहा था, जहां सामाजिक का विचार ही व्यक्तियों के हितों की देखभाल करने के लिए बनाई गई प्रणाली में सिमट गया था। शहरी क्षेत्रों में शॉपिंग मॉल इस सामाजिकता का एक शाब्दिक उदाहरण थे।

2.साहित्य की समीक्षा

2.1 आत्मानिर्भर भारत पर वैश्वीकरण का प्रभाव

वैश्विक स्तर पर व्यापार, निवेश और वित्त का विस्तार, एक तरफ, और दूसरी तरफ, सिकुड़ते स्थान, समय और सीमाओं को मिटाते हुए, लोगों के जीवन को पहले से कहीं अधिक तीव्रता से और तुरंत जोड़कर, वैश्विक स्तर पर व्यापार, निवेश और वित्त के विस्तार की विशेषता है। इसे बढ़ते व्यापार, नई तकनीकों, विदेशी निवेश, मीडिया के विस्तार और कनेक्टिविटी के माध्यम से दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए कई अवसर खोलने के रूप में भी देखा जाता है। यह भी तर्क दिया जा रहा है कि समकालीन वैश्वीकरण न केवल विस्तृत और व्यापक है बल्कि नए अभिनेताओं, नए नियमों, नए उपकरणों और नए बाजारों द्वारा संचालित किया जा रहा है। इसके निहितार्थ, संदेह से परे, दूरगामी हैं।वर्तमान समय में, वैश्वीकरण ने विद्वानों और आर्थिक विकास कार्यकर्ताओं से लेकर मानवाधिकार कार्यकर्ताओं तक, समूहों, हितों की एक विस्तृत श्रृंखला के काम की जानकारी दी है (पुरी 2017)।

एक बहुत उद्धृत मार्ग में, एंथनी गिडेंस इसकी बात करते हैं, "विश्वव्यापी सामाजिक संबंधों का गहनता जो दूर के इलाकों को इस तरह से जोड़ता है कि स्थानीय घटनाएं कई मील दूर होने वाली घटनाओं से आकार लेती हैं और इसके विपरीत।" जबकि वैश्विक आदान-प्रदान पर व्यापक सहमति है, हमारे पास वैश्वीकरण के चरित्र और परिणाम के काफी भिन्न आकलन हैं। कुछ लोगों के लिए, वैश्वीकरण की प्राथमिक विशेषता "विदेशीकरण" है, जो स्कोल्टे को "भूगोल का एक पुन: संयोजन" के रूप में वर्णित करता है, ताकि क्षेत्रीय स्थान, दूरी या सीमाओं के संदर्भ में सामाजिक स्थान को मैप नहीं किया जा सके। ओहर्स वैश्वीकरण के सांस्कृतिक आयाम पर जोर देते हैं (पुरी 2017)।

हालांकि, यह कहा जा सकता है कि स्थानीय संस्कृतियां न केवल प्रतिक्रिया करती हैं, बल्कि वैश्विक ताकतों के साथ द्वंद्वात्मक और प्रतिक्रियात्मक तरीकों से बातचीत करती हैं, यह भी उतना ही सच है कि वैश्वीकरण ने सांस्कृतिक समरूपता और एक वस्तु-संचालित, पश्चिम-केंद्रित वैश्विक संस्कृति के प्रभुत्व को प्रेरित किया है। एक आधिपत्य वाली विश्व व्यवस्था के साथ।वैश्वीकरण को अधिक विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश के माध्यम से देशों और घटनाओं के तेजी से एकीकरण की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है। यह विश्व के विचारों, उत्पादों, विचारों और संस्कृति के अन्य पहलुओं के आदान-प्रदान से उत्पन्न होने वाली अंतर्राष्ट्रीय एकीकरण की प्रक्रिया है (पुरी 2017)।

भारतीय उद्योग में वैश्वीकरण के विभिन्न लाभकारी प्रभाव यह हैं कि इसने उद्योग में विशेष रूप से बीपीओ, फार्मास्युटिकल, पेट्रोलियम और विनिर्माण उद्योगों में भारी मात्रा में विदेशी निवेश लाया। चूंकि भारतीय उद्योग में बड़ी मात्रा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) आ रहा था, उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को काफी बढ़ावा दिया।भारतीय उद्योग में वैश्वीकरण के प्रभावों का लाभ यह है कि कई विदेशी कंपनियों ने भारत में उद्योग स्थापित किए, विशेष रूप से दवा, बीपीओ, पेट्रोलियम, विनिर्माण और रासायनिक क्षेत्रों में और इससे देश में कई लोगों को रोजगार प्रदान करने में मदद मिली (स्क्रेसे 2015)।

इससे देश में बेरोजगारी और गरीबी के स्तर को कम करने में मदद मिली। साथ ही भारतीय उद्योग पर वैश्वीकरण के प्रभावों का लाभ यह है कि विदेशी कंपनियां अपने साथ अत्यधिक उन्नत तकनीक लाईं और इससे भारतीय उद्योग को तकनीकी रूप से अधिक उन्नत बनाने में मदद मिली।भारतीय उद्योग पर वैश्वीकरण के विभिन्न नकारात्मक प्रभाव यह हैं कि इसने विदेशी कंपनियों और घरेलू कंपनियों के बीच भारतीय बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ा दिया है। विदेशी वस्तुओं के भारतीय वस्तुओं से बेहतर होने के कारण उपभोक्ता विदेशी वस्तुओं को खरीदना पसंद करता था। इससे भारतीय उद्योग कंपनियों के लाभ की मात्रा कम हो गई (बीना 2014)।

यह मुख्य रूप से दवा, निर्माण, रसायन और इस्पात उद्योगों में हुआ।भारतीय उद्योग पर वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव यह है कि प्रौद्योगिकी के आने से आवश्यक श्रम की संख्या कम हो गई और इसके परिणामस्वरूप कई लोगों को उनकी नौकरियों से हटा दिया गया। यह मुख्य रूप से दवा, रसायन, विनिर्माण और सीमेंट उद्योगों में हुआ। भारतीय उद्योग पर वैश्वीकरण के प्रभाव सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही साबित हुए हैं। भारत सरकार को भारतीय उद्योग के वैश्वीकरण के संबंध में ऐसी आर्थिक नीतियां बनाने का प्रयास करना चाहिए जो लाभकारी हों और हानिकारक न हों (बाकन 2015)।

रोजगार में वृद्धि:

विशेष आर्थिक क्षेत्रों के खुलने से नई नौकरियों की उपलब्धता काफी प्रभावी रही है। इसके अलावा, हजारों लोगों को रोजगार देने वाले निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र या ईपीजेड भी स्थापित किए गए हैं। एक अन्य कारक भारत में सस्ता श्रम है। इसने पश्चिम की बड़ी फर्मों को इस क्षेत्र में मौजूद कंपनियों को काम आउटसोर्स करने के लिए प्रेरित किया है। ये सभी कारक अधिक रोजगार पैदा कर रहे हैं (स्क्रेसे,2015)।

मुआवजे में उछाल:

वैश्वीकरण के प्रकोप के बाद, मुआवजे का स्तर अधिक बना हुआ है। घरेलू कंपनियों ने जो प्रस्तुत किया है, उसकी तुलना में ये आंकड़े प्रभावशाली हैं। विदेशी कंपनियों द्वारा लाए गए ज्ञान और कौशल का स्तर स्पष्ट रूप से उन्नत है। इसके परिणामस्वरूप अंततः प्रबंधन संरचना में संशोधन हुआ है।

बेहतर जीवन स्तर और बेहतर क्रय शक्ति:

भारतीय शहरों में धन सृजन में वृद्धि हुई है क्योंकि वैश्वीकरण ने देश को पूरी तरह से प्रभावित किया है। आप व्यक्तियों, विशेष रूप से विदेशी संगठनों के तहत काम करने वालों के लिए क्रय शक्ति में सुधार देख सकते हैं। इसके अलावा, घरेलू संगठनों को अपने कर्मचारियों को उच्च पुरस्कार देने के लिए प्रेरित किया जाता है।

2.2 भारत को आत्मनिर्भर बनाने वाले कारक

सामाजिक कारक

उच्च शिक्षित और महत्वाकांक्षी युवाओं के एक बड़े पूल के साथ, भारत को स्वदेशी प्रतिभा को बढ़ावा देने वाले स्टार्ट-अप और स्वतंत्र उद्यमों की बढ़ती संख्या में एक फायदा है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), ग्रामीण स्वरोजगार और प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), आदि जैसी सरकारी योजनाएं ग्रामीण भारत के युवाओं को उद्योग-प्रासंगिक कौशल प्रशिक्षण सुरक्षित करने और नौकरी के अवसरों के लिए बड़े शहरों में प्रवास करने या अपना खुद का व्यवसाय स्थापित करने में सक्षम बनाती हैं (व्यापार 2017)। .

130 अरब की आबादी के साथ, भारत का एक मजबूत उपभोक्ता बाजार है। इसके अलावा, इंटरनेट के प्रसार और उपभोक्ता की बदलती आदतों ने घरेलू बाजार को बढ़ावा दिया है, उभरते उद्यमियों और स्टार्ट-अप का समर्थन किया है। इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण रिलायंस जियो की सफलता है जो एक ही देश के बाजार में 400 मिलियन ग्राहकों के मील के पत्थर तक पहुंचने में कामयाब रहा है।

भारत के पास कई अवसर और प्रचुर संसाधन हैं। उच्च स्तर के कौशल के साथ, यह उन कारकों में से एक है जिसने भारत को दुनिया का आईटी हब बना दिया है (खातून और इफ्फत)।

संरचनात्मक कारक

भारत मजबूत तकनीकी और इंजीनियरिंग क्षमताओं का दावा करता है जो भारत के युवाओं को शिक्षित करने की दिशा में काम करने वाले शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों द्वारा समर्थित हैं। सरकार ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नवाचार और अनुसंधान की बदलती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक नई शिक्षा नीति शुरू की है जिसका उद्देश्य भारत को एक ज्ञान महाशक्ति बनाना है। व्यावसायिक प्रशिक्षण पर भी एक नया ध्यान दिया जा रहा है, प्रतिभा पूल को और बढ़ाया जा रहा है (कुमारी 2016)।

सरकार द्वारा शुरू की गई प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) योजना भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने और निर्यात बढ़ाने पर केंद्रित है। यह योजना सफेद वस्तुओं के निर्माण, ऑटोमोबाइल, दूरसंचार, कपड़ा, खाद्य उत्पाद और दवा सहित 10 क्षेत्रों के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन प्रदान करती है। इस योजना का उद्देश्य निवेश को आकर्षित करना और भारतीय निर्माताओं को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है।

आर्थिक कारक

वह 'मेक इन इंडिया' अभियान घरेलू विनिर्माण उद्योगों को बढ़ावा देने और आयात पर निर्भरता कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट (पीपीई) निर्माण उद्योग की उपलब्धि एक नया बाजार स्थापित करने का अनुमान है जिसकी कीमत कम से कम रु। केवल दो महीनों में 10,000 करोड़ रुपये मेक इन इंडिया की सफलता की कहानी का एक अनुकरणीय उदाहरण है। इसने न केवल एक पूरी तरह से नए उद्योग को जन्म दिया है बल्कि भारत को एक आत्मनिर्भर और मजबूत राष्ट्र भी बनाया है। और अंदाज लगाइये क्या भारत अब मेडिकल पीपीई का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है। क्या यह प्रेरक नहीं है

भारत में कारोबारी माहौल अनुकूल है। हाल ही में विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 रिपोर्ट में 190 देशों में यह 63 वें स्थान पर है।

3.परिणाम और चर्चा

3.1 भारतीय व्यापार के वैश्वीकरण का प्रभाव

व्यापार के लिए भारत का जोखिम - जैसा कि जीडीपी में निर्यात और आयात हिस्सेदारी द्वारा मापा जाता है - 2018 के मध्य से काफी बढ़ गया है (चित्र 1)। 2018 की शुरुआत में टैरिफ में तेज कमी ने कुछ गैर-टैरिफ बाधाओं को खत्म करने के साथ मिलकर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। व्यापार के उद्घाटन ने उपभोक्ताओं के लिए नए अवसरों की पेशकश की है, जिन्होंने सामानों के व्यापक स्पेक्ट्रम तक पहुंच प्राप्त की है, और फर्मों के लिए, क्योंकि वे विश्व स्तरीय इनपुट आयात कर सकते हैं और अधिक प्रतिस्पर्धी बन सकते हैं। विदेशों से प्रतिस्पर्धा भी नवाचार के प्रसार की सुविधा प्रदान करती है और उत्पादकता की खोज को बढ़ावा देती है, एकाधिकार किराए पर दबाव डालती है (पुलिचेरला 2011)।

व्यापार के लिए अधिक खुला होने के बाद से, भारत का निर्यात और आयात-से-जीडीपी अनुपात तेजी से बढ़ा और अब मोटे तौर पर चीन के बराबर है। हालांकि कुल निर्यात में सेवाओं का बड़ा हिस्सा बाहर खड़ा है। 2020 के उत्तरार्ध से निर्यात-से-जीडीपी अनुपात में वृद्धि आंशिक रूप से उलट गई है क्योंकि भारत और कई अन्य ईएमई को सुस्त वैश्विक मांग और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (एई) द्वारा कुछ री-शोरिंग का सामना करना पड़ा है। भारतीय निर्यात को भी रुपये

की सराहना और 2020 के विमुद्रीकरण और माल और सेवा कर (जीएसटी) के रोल आउट से जुड़ी घरेलू मूल्य श्रृंखलाओं में अस्थायी व्यवधानों का सामना करना पड़ा। कुल मिलाकर, निर्यात प्रदर्शन, इस बात से मापा जाता है कि भारत का निर्यात उसके बाजार विकास के सापेक्ष कितना बढ़ा है, ठोस बना हुआ है (भट्टाचार्जी 2011)। वस्तुओं और सेवाओं के विश्व निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 2018 की शुरुआत में 0.5% से बढ़कर 2020 में 2.1% हो गई।

वर्गीकरण	माइक्रो	छोटा	मध्यम
एमएफजी उद्यम	निवेश < Rs 25 lac	निवेश < Rs 5 cr.	निवेश< Rs 10 cr.
सेवा उद्यम	निवेशt < Rs 10 lakh	निवेश < Rs 2 cr	निवेश < Rs 5 cr.
	Revised MSME Classification		
	Composite Criteria:Investment and Annual Turnover		
वर्गीकरण	माइक्रो	छोटा	मध्यम
विनिर्माण और सेवाएं	निवेश < Rs 1 cr and Turnover< Rs 5 cr	निवेश < Rs 10 cr and Turnover < Rs 50 cr.	निवेश < Rs 20 Cr and Turnover < Rs 100cr.

तालिका 1: एमएसएमई की मौजूदा और संशोधित परिभाषा

(स्रोत: लेखक द्वारा निर्मित)

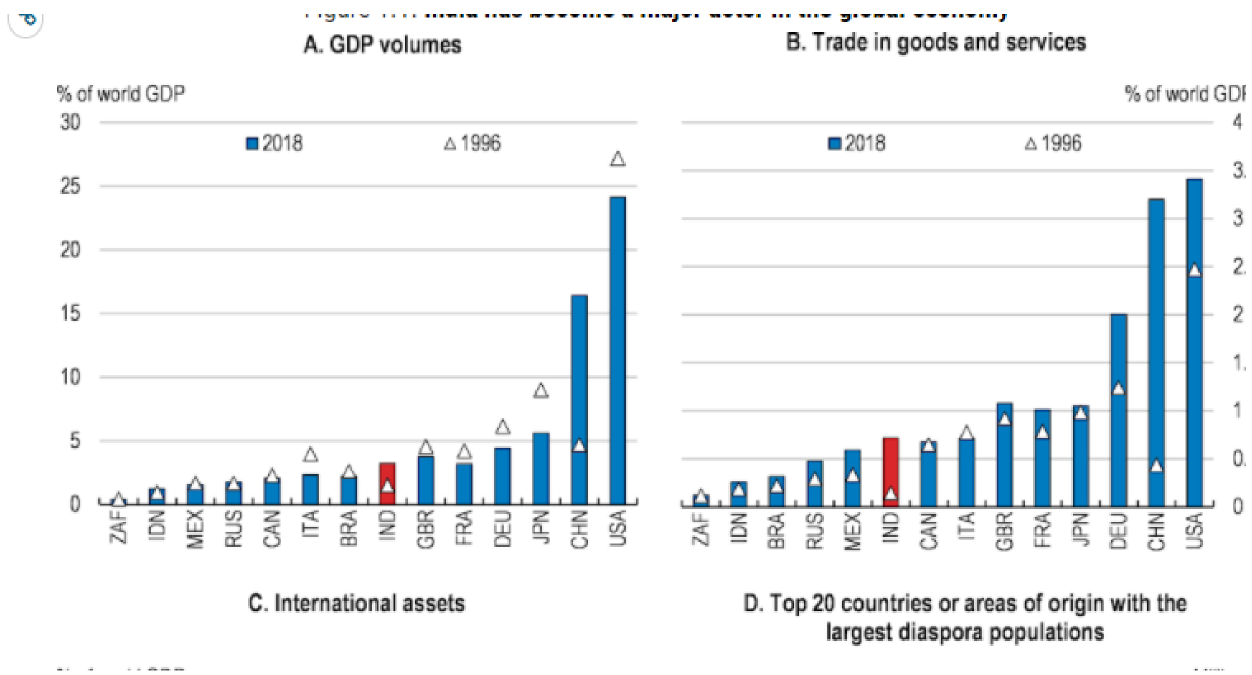

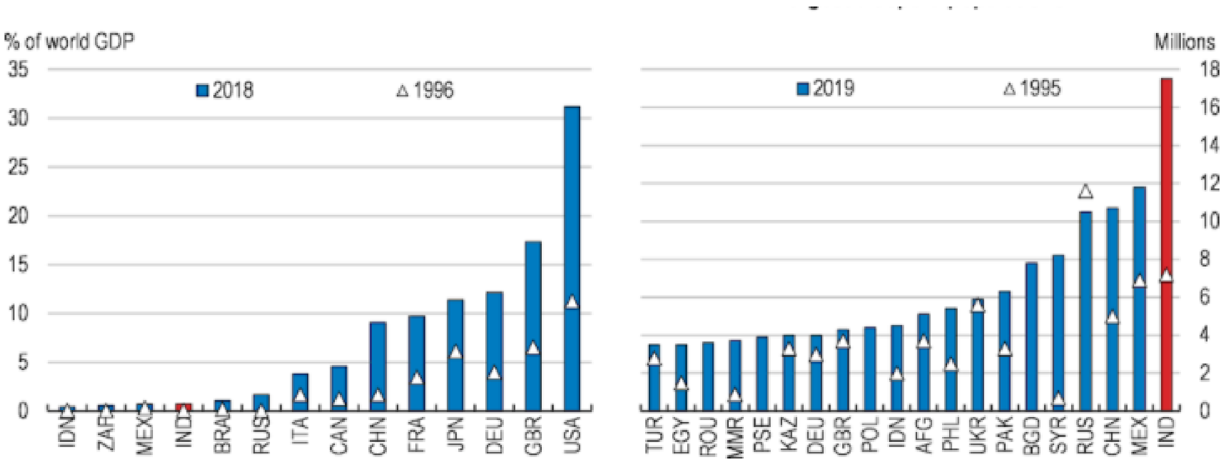

चित्र 1: व्यापार पर आत्मनिर्भर भारत का प्रभाव

(स्रोत; लेखक द्वारा निर्मित)

भारत कृषि उत्पादों का निर्यातक है और कृषि वस्तुओं में इसका व्यापार अधिशेष बढ़ा है। भारत में कृषि नीतियों की हालिया ओईसीडी/आईसीआरआईईआर समीक्षा से पता चलता है कि खाद्य क्षेत्र में मूल्य श्रृंखला अपेक्षाकृत कम विकसित(ओईसीडी/आईसीआरआईईआर) बनी हुई है। यह निष्कर्ष निकालता है कि भारत के लिए एक अधिक परिष्कृत घरेलू प्रसंस्करण और वितरण उद्योग विकसित करने और कुछ कृषि वस्तुओं के निर्यात के लिए अपने तुलनात्मक लाभ का पूरी तरह से दोहन करने के लिए एक अधिक खुली और स्थिर व्यापार नीति व्यवस्था आवश्यक है (कुमारी 2021)।वैश्वीकरण का पूरा लाभ उठाने के लिए, विशेष रूप से नौकरी और आय सृजन में वृद्धि, फर्मों के सामने आने वाली बाधाओं को दूर करने की आवश्यकता होगी। घरेलू अड़चनें सभी कंपनियों को प्रभावित करती हैं, चाहे वे वास्तव में निर्यात करती हों या नहीं। अन्य बाधाएं व्यापार के लिए विशिष्ट हैं, जिसमें व्यापार बुनियादी ढांचे और रसद शामिल हैं।

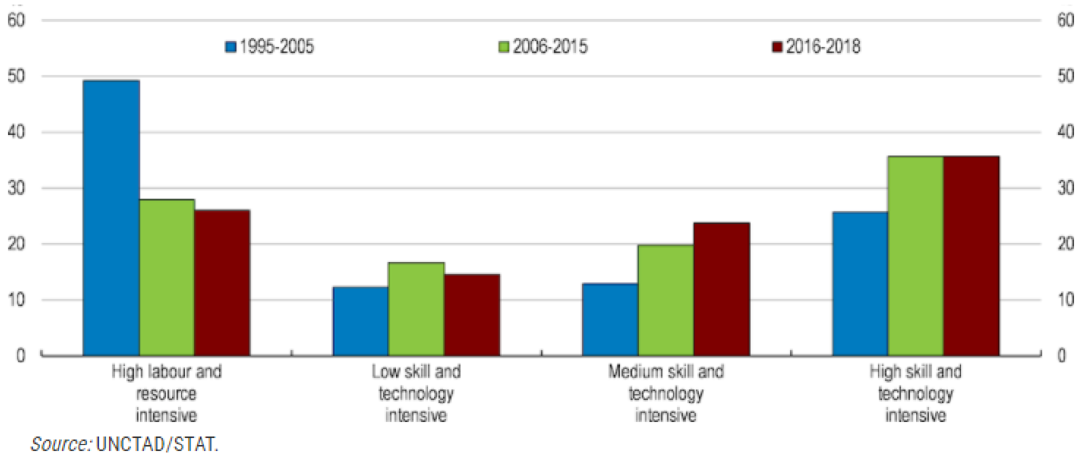

चित्र 2: आत्मनिर्भर भारत पर वैश्वीकरण का प्रभाव

(स्रोत; लेखक द्वारा निर्मित)

आत्मनिर्भरता एक अर्थव्यवस्था को अंतरराष्ट्रीय बाजार से आवश्यक मदद लेने की अनुमति देती है, जो आत्मनिर्भर के मामले में नहीं देखी जाती है। विकास का अधिक प्रगतिशील तरीका आत्मनिर्भर बनने के बजाय आत्म-निर्भरता के कठोर तरीकों के साथ खड़े होने में सक्षम होने के अविश्वास में रहना है (रामकृष्णन, 2011)। उदारीकरण ने भारतीय उद्योगों को फलने-फूलने और उपायों से परे हासिल करने की अनुमति दी। विकास के अवसर बढ़े, और 1991 से पहले बनाया गया खोल वैश्वीकरण के पहले प्रारंभिक चरणों के साथ खुला हो गया। भारतीय रक्षा अर्थव्यवस्था एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के रूप में कार्य करने के भार में फंस गई थी। जैसे ही इसे हटा दिया गया, विश्व स्तर पर अन्य अर्थव्यवस्थाओं द्वारा औद्योगीकरण की वास्तविक क्षमता देखी गई। यह लेख परिवर्तन अवधि के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था द्वारा देखे गए महत्वपूर्ण मील के पत्थर पर प्रकाश डालेगा। भारतीय रक्षा अर्थव्यवस्था के समृद्ध इतिहास और फलते-फूलते वैश्वीकरण को संक्षेप में प्रस्तुत किया जाएगा।

बेस केस परिदृश्य के तहत क्षेत्रों द्वारा जीवीए वृद्धि	वर्ष 2019-20 में वर्ष दर वर्ष वृद्धि (% में)	साल दर साल वृद्धि 2020--21 में (% में)
उद्योग	2	-25
कृषि	1	-4
सेवा	5	-9
कुल	8	13

तालिका 2: विभिन्न क्षेत्रों में आत्मनिर्भर भारत का प्रभाव

(स्रोत: लेखक द्वारा निर्मित)

निष्कर्ष के साथ, पाठक भारतीय अर्थव्यवस्था की एक स्वस्थ तस्वीर की एक स्पष्ट तस्वीर खींचेगा। आत्मानिर्भर भारत अधिकांश श्रम शक्ति की आय और उत्पादकता में सुधार पर निर्भर करता है। इसे करने के दो तरीके हैं। सबसे पहले, कृषक समुदाय को अनाज आधारित खेती से नकदी फसलों, बागवानी और पशुधन उत्पादों में स्थानांतरित करने के लिए प्रोत्साहित करें। चीनी अनुभव से पता चलता है कि 1970 के दशक के अंत में कृषि में सुधार से ग्रामीण आय में वृद्धि हुई, जिससे श्रम-प्रधान औद्योगिक वस्तुओं की मांग बढ़ी, जो चीन की विनिर्माण सफलता की शुरुआत थी। दूसरा, श्रम शक्ति को कृषि से विनिर्माण क्षेत्र में स्थानांतरित करना। भारत केवल तभी आत्मनिर्भर बन सकता है जब वह अपने सर्वोत्तम दान - 27 वर्ष की औसत आयु के साथ कामकाजी उम्र की आबादी में 900 मिलियन लोगों का उपयोग करता है - और चीन के रूप में अपने जनसांख्यिकीय लाभांश को विनियोजित करता है । यह तभी संभव है जब श्रम प्रधान विनिर्माण बड़े पैमाने पर हो, कम या कम कौशल वाले श्रम बल के लिए रोजगार के अवसर पैदा करें, आय और मांग पैदा करें। भारत ऐसे समय में एक अद्वितीय स्थिति में है जब अन्य सभी विनिर्माण दिग्गज क्रमिक रूप से बूढ़े हो रहे हैं - जापान, यूरोपीय संघ, अमेरिका और यहां तक कि दक्षिण कोरिया और चीन। इनमें से अधिकांश देश निम्न-श्रेणी के श्रम-प्रधान विनिर्माण से बाहर हो गए हैं, और वह स्थान बांग्लादेश, वियतनाम, मैक्सिको आदि जैसे देशों द्वारा लिया जा रहा है।

निष्कर्ष

आत्मानिर्भर भारत अभियान या आत्मनिर्भर भारत अभियान माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा परिकल्पित नए भारत की दृष्टि है। 12 मई 2020 को, हमारे प्रधान मंत्री ने आत्मानबीर भारत अभियान (आत्मनिर्भर भारत अभियान) को एक किक स्टार्ट देते हुए राष्ट्र के लिए एक स्पष्ट आह्वान किया और INR 20 लाख करोड़ के विशेष आर्थिक और व्यापक पैकेज की घोषणा की - जो भारत के 10% के बराबर है। जीडीपी - भारत में COVID-19 महामारी से लड़ने के लिए।इसका उद्देश्य देश और उसके नागरिकों को हर तरह से स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाना है।

संदर्भग्रंथ

1. आहूजा, आई.पी.एस., 2011। एक संगठन में मुख्य क्षमता निर्माण के लिए अनुसंधान और विकास का प्रबंधन। जर्नल ऑफ़ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एंड इनोवेशन, 6(1), पीपी.58-65।
2. हयात, पी., 2016. स्मार्ट सिटीज: एक वैश्विक परिप्रेक्ष्य। इंडिया क्वार्टरली, 72(2), पीपी.177-191।
3. ओटो-ज़िम्मरमैन, के. एड., 2011. रेजिलिएंट सिटीज़: सिटीज़ एंड अडेप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज-प्रोसीडिंग्स ऑफ़ द ग्लोबल फ़ोरम 2010 (वॉल्यूम 1)। स्प्रिंगर साइंस एंड बिजनेस मीडिया।
4. बरगवी, एन., सैमुअल, ए.ए. और पॉल, पी.जे.डी., 2017. भारतीय आईटी उद्योग में सहस्राब्दी नेताओं का लचीलापन। इंडियन एकेडमी ऑफ एप्लाइड साइकोलॉजी का जर्नल, 43(2), पीपी.211-221।
5. क्रूज़, एस.ओ., 2015. वैश्विक शासन का वैकल्पिक वायदा: वैश्विक दक्षिण से परिदृश्य और दृष्टिकोण। दूरदर्शिता।
6. Dehghanpour, K., Colson, C. और Nehrir, H., 2017. लचीला/स्व-उपचार ग्रिड के लिए स्मार्ट एजेंट-आधारित माइक्रोग्रिड पर एक सर्वेक्षण। एनर्जीज, 10(5), पी.620।
7. पुरी, एल.एम., 2017. कार्य के भविष्य में संक्रमण-संभावना की शक्ति। जिंदल जे पब्लिक पॉलिसी, 5(1), पीपी.16-29.
8. व्यापार, एस।, 2017. साधारण व्यवसाय। निदेशक, 99, पीपी.0-16।
9. स्क्रेसे, टी.जे., रटन, एम., गांगुली-स्क्रैस, आर. और ब्राउन, टी., 2015. महानगर से परे - भारत में क्षेत्रीय वैश्वीकरण और शहर विकास: एक परिचय। साउथ एशिया: जर्नल ऑफ साउथ एशियन स्टडीज, 38(2), पीपी.216-229।
10. बीना, पीएल, 2014। विलय और अधिग्रहण: वैश्वीकरण के तहत भारत। रूटलेज।
11. बाकन, एस. और यिल्डिरिमसी, ई., 2015. ए ग्रोथ स्टोरी: वैश्वीकरण, बहुराष्ट्रीय कंपनियां और भारत। जर्नल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट स्टडीज, 3(3), पीपी.143-153।
12. रामकृष्णन, एस।, 2021. बाल चिकित्सा कार्डियोलॉजी: क्या भारत आत्मनिर्भर है?। एनल्स ऑफ पीडियाट्रिक
13. पुलिचेरला, के.के., अडापा, वी., घोष, एम. और इंगल, पी., 2011। "आत्मनिर्भर भारत" बनाने के लिए "मेक इन

14. इंडिया" के पूरक के लिए विनिर्माण क्षेत्र में सतत हरित विकास पर वर्तमान प्रयास। पर्यावरण अनुसंधान, पी.112263.

15. . कुमारी, डी., 2011. महामारी परिदृश्य के तहत भारत के सतत विकास के लिए संसाधन प्रबंधन और आत्मनिर्भरता की समीक्षा। SSRN 3937480 पर उपलब्ध है।

16. 1भट्टाचार्जी, सी., 2012। आत्मानबीर भारत: वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करना।